



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 4, 2007/वैशाख 14, 1929

No. 526]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 4, 2007/VAISAKHA 14, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2007

का.आ. 717(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ), अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और, यतः, असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 किमी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है :-

- (i) असम राज्य में, हेलाकण्डी एवं करीमगंज जिलों को छोड़कर, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति मुख्यतः यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोरोलैण्ड (एनडीएफबी), कर्बी लोंगरी एन सी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ), दीमा हलाम दाओगाह (डीएचडी) और डीएचडी के जोयल गारलोसा गुट की हिंसक गतिविधियों के कारण बिगड़ी रही है।

- (ii) असम में नवंबर, 2006 और 31 मार्च, 2007 के बीच हुई 238 घटनाओं में भूमिगत गुटों द्वारा 12 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 156 व्यक्तियों की हत्याएं की गईं।
- (iii) असम की सीमा से लगी अरुणाचल प्रदेश की 20 कि.मी. पट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और असम में सक्रिय विभिन्न भूमिगत गुटों की हिंसक गतिविधियों के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आई है। उल्फा भी इस क्षेत्र का प्रयोग अपने छुपने के अड्डे बनाने के लिए कर रहा है। सुरक्षा बलों ने उल्फा के काइरों को मार गिराने और उनकी गिरफ्तारी करने के अलावा इस क्षेत्र में कई परित्यक्त शिविरों का पता लगाया है। इसके अतिरिक्त नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एनएससीएन) के दो गुट और एनडीएफबी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और जबरन धन वसूली करके निधियों को एकत्र कर रहे हैं।
- (iv) असम की सीमा से लगे मेघालय राज्य की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी का भूमिगत गुटों द्वारा पड़ोसी देशों से/को घुसपैठ /बाहर जाने के मार्ग के रूप में और गारो हिल्स पट्टी से होकर असम को शस्त्र एवं गोलाबारूद की तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि असम की सीमा पर जब कभी विद्रोह विरोधी अभियानों को तीव्र किया जाता है तो विद्रोही गुट गारो पहाड़ियों में चले जाते हैं जहाँ उनके आश्रय स्थल हैं।

अतः, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 4.11.2007 तक 'अशान्त क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एनई-IV]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th May, 2007

S.O. 717(E).— Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification SO 916 (E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya, along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the period during which the State of Assam and areas falling within 20 KMs wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya, bordering Assam indicates the following:-

- i) The law and order situation in the State of Assam except Hailakandi and Karimganj districts has remained vitiated mainly due to violent activities of the United Liberation front of Asom (ULFA), National Democratic Front of Boroland (NDFB), Karbi Longri NC Hills Liberation Front (KLNLFF), Dima Halam Daogah (DHD) and Joel Garlosa faction of DHD.

- ii) Between November 2006 and upto 31st March 2007, as many as 156 persons including 12 Security Force personnel were killed by the Under Ground outfits in 238 incidents of violence in Assam.
- iii) The areas falling in 20 Km belt inside Arunachal Pradesh bordering Assam has witnessed deterioration in law & order situation due to violent activities of different Under Grounds outfits operating in Arunachal Pradesh and Assam. This area is also used by ULFA for establishing hideouts. Security Forces have unearthed many abandoned camps of ULFA in this area besides killing and arresting its cadres. In addition, the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) and NDFB are active in this area and have been accumulating funds through extortions.
- iv) The 20 Kms wide belt in the State of Meghalaya bordering Assam continue to be used by Under Ground outfits as an infiltration/exfiltration routes from/to neighbouring countries and for smuggling of arms and ammunition to Assam via Garo Hills belt. It has also been noticed that whenever Counter Insurgency operations are intensified on the Assam border, the insurgents retreat to the Garo Hills where they have shelters.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the States of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto 4.11.2007 unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]
NAVEEN VERMA, Jt. Secy.